IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता

Prof. Neetu Kumari
Assistant Professor,
Department of Legal studies
Jharkhand Rai University, Ranchi

सार - यह अध्ययन कार्ल मार्क्स के विचारों की प्रासंगिकता का विश्लेषण करता है। राजनीति, देश के विकास के लिए बनाई गई हित की नीतियों के इर्द – गिर्द घूमती है और नीतियाँ बिना मुद्रा के संचालित नहीं हो सकती। अर्थात् मुद्रा, नीतियों का ईंधन है। राजकोषीय नीति और मुद्रा नीति को संचालित करके ही देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स के कई कथन के असत्य होने मे बावजूद भी किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास उनके विचारों के बिना संभव नहीं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को गलत दिशा मे जाने से बचाया है तथा आज भी विश्व अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने मे उनके विचारों की प्रासंगिकता झलकती है।

मुख्य शब्द – मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद, पूंजीवाद, एकाधिकार, राजकोषीय नीति

I.परिचय:-

कार्ल मार्क्स के जन्म का 205 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब भी उनके विचारों की बात आती है तो विशेषज्ञों मे वाद – विवाद छिड़ जाते हैं । कई संपादकीय पत्र इनके विचारों को लेकर लिखा जाता रहा है। आज भी अनेक विद्वानों ने इनके विचारों को प्रासंगिक मानते हैं तो कई विद्वानों का मत है कि कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी असत्य साबित हुई, अतः यह अप्रासंगिक है।

लेकिन जब भी बात क्रांति या बदलाव की आती है, मजदूरों व किसानों की हक की बात आती है तथा आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा होती है, तो विशेषज्ञों के द्वारा कार्ल मार्क्स के विचारों के पन्ने पलटे जाने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं जब विश्व के अनेक देशों के द्वारा औपनिवेशिक गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया जा रहा था तो उनका 'एनर्जी पॉवर' कार्ल मार्क्स के विचार ही थे।

हाँ, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई भविष्यवाणी पूर्णतः सत्य नहीं हो पाई क्योंकि जब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत वास्तविकता मे सामने आई तो शासन व्यवस्था अधिनायकतंत्र का रूप ले लिया, सम्पूर्ण शक्ति किसी एक के हाथों मे चली गई तथा प्रजातन्त्र का अंश तक नहीं बचा। कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई भविष्यवाणी आम जनता के लिए थी, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए था, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए था। और इसका प्रभाव हम सभी आर्थिक मंदी के समय देख सकते है। अगर मुद्रा का ज्यादातर हिस्सा कुछेक पूंजीपतियों के हाथों मे चली जाएगी और मुद्रा का बहुत कम हिस्सा मध्यम / गरीब वर्ग के पास होगा तो किसी देश का अर्थव्ययवस्था कुछ समय के लिए ऊपर तो जाएगी लेकिन बहुत ही जल्द नीचे गिर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पूंजीपति विलासिता वस्तुओं को कितना खरीददारी करेगा वो एक समय पर उसकी मांग कम हो जाएगी, जैसे – मकान, कार आदि । लेकिन मध्यम / गरीब वर्ग जिनकी संख्या पूँजीपतियों से कई गुणा ज्यादा है उनकी मौलिक वस्तुओं की मांग हर रोज होगी। अतः किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास होता रहे इसके जरूरी है कि मुद्रा का बंटवारा बहुत ज्यादा या कम – ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होने की स्थिति पैदा हो जाए तो सरकार को समाजवादी विचारधारा को लागू करने मे नहीं हिचकिचाना चाहिए। अलगाववादिता की भावना अक्सर क्रांति की स्थिति पैदा करती है ऐसा हो उससे पहले जड़ से समस्याओं का समाधान कर दिया जाना चाहिए ।

II. अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत

कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वर्ग संघर्ष के तार्किक आधार का संकेत देता है। जहां ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्सवाद का सामाजिक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है, वहीं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्सवाद का आर्थिक आधार हमारे सामने रखता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से पूंजीवाद के अंतर्गत कामगारों के शोषण की प्रकृति को स्पष्ट करता है।

मार्क्स वस्तु के मूल्य को दो भागों मे बांटते हैं – प्रथम उपयोग मूल्य अर्थात् उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर निर्धारित मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य अर्थात क्रेता द्वारा विक्रेता से खरीदे जाने वाला मूल्य । मार्क्स की मान्यता है कि जब किसी प्राकृतिक पदार्थ पर मानव श्रम व्यय का व्यय होता है तो यह मानव श्रम उसका विनिमय मूल्य पैदा करता है ।

जिस प्रकार माल, उपयोग और विनिमय मूल्यों का सम्मिश्रण है, उसी तरह माल उत्पादन की प्रक्रिया, श्रम प्रक्रिया और मूल्य सृजन करने वाली प्रक्रिया का सम्मिश्रण है। मूल्य सृजन करने वाली प्रक्रिया उस जगह चलती रहती है जहां मजदूरों के रूप मे चुकाये गए श्रम- शक्ति के मूल्य का स्थान मात्रा वाला मूल्य ले लेता है। इस स्थान से परे, वह अतिरिक्त मूल्य उत्पादन करने की प्रक्रिया उपयोग करने की प्रक्रिया के रूप में विकसित होता है । वह श्रम प्रक्रिया और उपयोग करने की प्रक्रिया, माल उत्पादन का पूंजीवादी रूप बन जाता है।

उदाहरण के लिए कपास की गठरी किसानों से रु 500 में खरीद कर लाया जाता है, और उस पर श्रमिक अपना श्रम लगाकर कपड़ा का बंडल बनाकर तैयार करते हैं,जिसे फैक्ट्री का मालिक रु 2500 में बेच देता है जबकि इस श्रम के लिए फैक्ट्री का मालिक केवल वेतन के रूप मे रु 500 श्रमिक को देता है, इस प्रकार,

लागत = कपास का मूल्य + मजदूरी

500 + 500 = 1000

कपड़े का बंडल का मूल्य (विक्रय मूल्य)= 2500

फैक्ट्री मालिक का लाभ = 2500-1000= 1500 रु

ये 1500 रु जो बचे हैं, वह केवल फैक्ट्री मालिक को लाभ हुआ है। मार्क्स के अनुसार यह मालिक का लाभ अतिरिक्त मूल्य है जो एक पूंजीपति अपने हक से ज्यादा पैसा प्राप्त कर रहा है और एक मजदूर को उसका मौलिक वेतन भी नहीं मिल पाता है।इस प्रकार, समाज मे अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस तरह के पैसों का बंटवारा से गरीब वर्ग, जो संख्या में ज्यादा होते है, के द्वारा मांग मे कमी आती है और अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाती है। यहाँ कार्ल मार्क्स का भविष्यवाणी था कि ऐसी स्थिति मे वर्ग संघर्ष शुरू हो जाएगा और पूंजीपति वर्ग अपने आप लुप्त हो जाएंगे। और ये भविष्यवाणी गलत हुआ इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था।

III. विश्व का महान आर्थिक मंदी (1929) और कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव

पश्चिमी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया जो फ्री मार्केट पॉलिसी पर आधारित होता है, वहाँ की सरकार का मार्केट मे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जब 1929 मे विश्व मे आर्थिक मंदी आई तब समझना काफी मुश्किल था कि आखिर इतनी बड़ी मंदी आई कैसे ? और इससे निकालने के लिए क्या उपाय किया जाए ? एक अंग्रेज अर्थशास्त्री John Maynard Keynes ने 'The general theory of Employment, Interest and money, 1936' की रचना की । अपने इस कृति के द्वारा 'Laissez-faire' और 'invisible hand' की प्रकृति पर सवाल करना शुरू किए और इस व्यवस्था को Strangulating of poor की उपाधि से नवाजा। वह आगे सलाह देते है कि ऐसी परिस्थिति से उभरने के लिए सरकार को सशक्त रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, और सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति का आविर्भाव किया जाए ताकि बाजार मे जनता के द्वारा मांग की बदोतरी हो। पश्चिमी देशों की सरकारों के द्वारा इस सलाह को माना भी गया। इस प्रकार से, कीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार विश्व के सामने रखा जो पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रित रूप है, भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, कीन्स का मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को

समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाने चाहिए ताकि मंदी की स्थिति पैदा ना हो सके। एक पश्चिमी विचारक ने पूरी ना सही लेकिन मार्क्स के मौलिक विचारों को अपनाया और नई विचार का प्रतिपादन किया।

लेकिन स्थिति मे सुधार लाना इतना आसान नहीं था, समय समय पर आर्थिक मंदी देखा जाता रहा है। जब भी समाज मे अमीरी – गरीबी की खाई बढ़ेगी और खरीददारी में कमी आएगी, हमें मंदी की स्थिति देखने को मिलेगा। फिर से पूंजीवादी दुनिया 1940 मे एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की

अर्थव्यवस्था पर इस संकट का सबसे ज्यादा असर पड़ा था। वाशिंगटन के शासकों ने दावा किया कि मार्शल योजना और हथियार के कार्यक्रम की मदद से इस संकट से अमेरिका को निकाल लेंगे, लेकिन यह संभव न हो सका। ट्रूमैन सरकार ने फैसला लिया कि आर्थिक आंकड़ों को बदल दिया जाए, जो कि कहीं ज्यादा आसानी से किया जा सकता था, लेकिन झूठे बनाए हुए सूचना अंक, वे चाहे सबसे ऊपर क्यूँ णा हो, बढ़े हुए व्यापारिक व्यवहार की जगह नहीं ले सकता। अतः 'जर्नल ऑफ कॉमर्स' 24 नवंबर को लिखा कि सरकार ने आकड़ों को घूमने- फिरने में जो हस्थ- लाघव दिखाया है उसे 'आकड़ों के बारे मे इस साल की सबसे बढ़िया हाथ की सफाई का सर्टिफिकेट मिल मिल सकता है।'

ब्रिटेन के आयात- निर्यात व्यापार का अनुपात भी बदतर होता जा रहा था। पश्चिमी यूरोपीय देशों मे औद्योगिक पैदावार में, जो 1948 से 1949 के शुरू में ही एक ही जगह टिकी हुई थी , मार्च – मई 1949 से गिरावट की प्रवृति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम आदि सबके अर्थव्यवस्था नीचे गिर गया था।

पूंजीवाद यूरोप और अमेरिका की स्थिति को सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति से तुलना करते हुए जी. एम. मलेनकोव कहते हैं – 'यह कहा जा सकता है कि दुनिया मे परिस्थिति ऐसी है कि उन देशों और लोगों का काम – काज अच्छी तरह से हो रहा है जो अमेरिका की तथाकथित मदद के बिना चल रहे हैं, और हमें विश्वास है कि समय बिताने के साथ साथ वह और भी अच्छा होता जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका का और उन देशों का जिनका 'वह मदद कर रहा है काम- काज बद से बदतर होता जा रहा है।'[4]

BBC News के एक रिपोर्ट के अनुसार – पूंजीवाद के पिता एडम स्मिथ के 'wealth of nation' से उलट मार्क्स का मानना था कि बाजार को चलाने मे किसी अदृश्य शक्ति की भूमिका नहीं होती, बल्कि वह कहते हैं कि मंदी का बार बार आना तय है , इसका कारण पूंजीवाद मे ही निहित है। 1929 मे शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया और इसके बाद आने वाले झटके 2007-2008 मे चरम तक पहुँच गए, तब दुनिया का वित्त बाजार अभूतपूर्व रूप से संकट मे आ गया था। मार्क्स का मानना था कि जब भी पूंजी कुछ चंद हाथों में केंद्रित होती जाती है तो इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ती है और मजदूरी मे गिरावट आती जाती है।

यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि कार्ल मार्क्स अर्थशास्त्री रिकार्डो से प्रभावित थे, लेकिन उनके सारे विचारों का समर्थन नहीं करते थे। अर्थशास्त्री रिकार्डो एडम स्मिथ से प्रभावित थे लेकिन कुछ विचारों की वे आलोचना भी करते है और बाद में, कीन्स ने मंदी से उभरने के लिए आंशिक रूप से समाजवाद का समर्थन करते है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार विश्व के सामने रखते है।

IV. निष्कर्ष -

कार्ल मार्क्स के पास इतनी काबिलियत थी जिससे कि वह अपना सम्पूर्ण जीवन सुखमय गुज़ार सकते थे लेकिन फिर भी मार्क्स ने मजदूरों व गरीबों के उद्धार के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिए। काफी आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने ऐसे विचारधारों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो सर्वथा सत्य एवं अडिग है। जिस समयकाल में मजदूरों को तुच्छ समझा जाता था, औद्योगिक क्रांति में अंधे होकर यूरोपीय देशों की सरकार एक बड़े तबके मजदूर वर्ग पर अन्याय कर रहे थे। उस काल मे कार्ल मार्क्स ने कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने का बेड़ा उठाया। यह कार्य किसिस साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता था।

मेरा मानना है कि कार्ल मार्क्स के विचारों को वास्तविकता में जोड़ -तोड़ के पेश किया गया। चीन जो खुद को साम्यवादी देश मानता है, वहाँ 14 मई 1989 के नरसंहार में हजारों लोग मारे गए थे क्योंकि चीन के थियानमेन चौक पर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। मार्क्स ने ऐसे शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं की थी, वे तो एक पत्रकार थे जो हमेशा आम जनता के पक्ष मे खड़ा रहते थे। मार्क्स कहते हैं, **'Democracy is the road of socialism.'** जब मार्क्स ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तब उस समय की स्थिति ही ऐसी थी कि पूंजीपति केवल पैसों के बारे मे सोच रहे थे, उनके अंदर की मानवता खत्म सी हो गई थी। ऐसे मे एक बड़े तबके वर्ग की मस्तिष्क में अलगाव की भावना पनपना स्वभाविक था जो किसी भी समाज के विकास के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। मार्क्स ने इन बुराइयों को खत्म करने के लिए साम्यवाद की स्थापना की बात कहीं।

पूंजीवाद और समाजवाद एक हीं तराजू के दो पलड़े हैं जो समाज को संतुलित करता है। यदि समाजवाद का अंत कर दिया जाए तो फिर से एक बड़ा तबका अलगाववाद की स्थिति में आ जाएगा जो किसी समाज के विकास के सही नहीं है। **राहुल सांकृत्यायन** अपने पुस्तक **'साम्यवाद ही क्यों?'** में इस बात का जिक्र किए हैं, वह बताते है हैं कि जो समाज में कुरीतियाँ, बुराइयाँ, जातीयता, लैंगिक भेदभाव तथा वर्गों की उत्पति हुई है,उसके दमन के लिए साम्यवाद की आवश्यकता है।

जिस परिस्थिति मे मार्क्स ने भविष्यवाणी किया था वो सही था लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हो उससे पहले ही हालात को अलग दिशा मे मोड़ दिया गया और वो भी कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी की वजह से ही ऐसा किया गया। विश्व के विभिन्न देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए वहाँ की सरकार बाजार में हस्तक्षेप करती है ताकि मार्क्स के कथन सत्य ना हो जाए । भारत की बात करें तो भारतीय संविधान मे DPSP का प्रावधान किया गया है, समय -समय पर सरकार शासन व्यवस्था पर हस्तक्षेप कर स्थिर बनाए रखेगी। हाल में ही देखा गया जब Jio telecom company भारतीय बाजार मे एकाधिकार करने की कोशिश मे थी तब सरकार ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संतुलित रखी। ऐसी परिस्थितियां अक्सर देखने को मिलती रहती जहां यह साबित हो जाता है कि पूंजीवाद के विचारों से मात्र अर्थव्यवस्था को संतुलित नहीं रखा जा सकता हैं।

References *:-*

1. बेनीपुरी रामवृक्ष, कार्ल मार्क्स, गार्गी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1951
2. सांकृत्यायन राहुल, कार्ल मार्क्स, किताब महल, इलाहाबाद, 1988
3. शर्मा श्रीराम आचार्य, मानवीय समता के प्रतिष्ठता महर्षि कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय साम्यवाद प्रोपेगेंडा विभाग द्वारा मुद्रित , नई दिल्ली
4. ए मैनुकयान, न्यू टाइम्स, 1 जनवरी 1940 के अंक से
5. सांकृत्यायन राहुल, साम्यवाद ही क्यों?, किताब महल, इलाहाबाद, 1943
6. https://www.investopedia.com/terms/k/keynesianeconomics.asp
7. Karl Marx: His Books, Theories, and Impact (investopedia.com)
8. https://www.deccanherald.com/opinion/panorama/burdened-telecom-sector-awaits-government-intervention-1029655.html